

श्री बड़े : जब लेट आए हैं तो भी आपने मंजूर किये हैं। मैं निकाल कर आपको बता दूंगा। प्रेसिडेंट्स इसके बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप गैर हाजिरी की बात कर रहे हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salem-pur): I move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

“This House, having considered the present economic situation in the country, approves the steps taken by the Government of India thereon and urges the Government of India to take effective steps to control the price line and to effect economy at all levels of administration and public expenditure.”

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय हम नहीं चाहते कि आप की आज्ञा का उल्लंघन किया जाये। हम तो आप की आज्ञा को अमर बनाने के लिए यहां बैठ हुए हैं। हम बीच में कोई ऐसी बात पैदा नहीं करना चाहते हैं, जिस से पार्लियामेंट का डेकोरम खराब हो।

Shri C. K. Bhattacharyya: The decision that the Finance Minister has taken in devaluing the rupee at the present juncture is one of the boldest and the most honest steps that he could have taken. The criticisms that my hon. friends opposite have made against this measure....

Mr. Speaker: He might continue his speech tomorrow.

17 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-EIGHTH REPORT

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): I beg to present the Forty-eight Report of the Business Advisory Committee.

17.01 hrs.

*PROCUREMENT LEVY SCHEMES OF STATES

श्री मधु लिमय : (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, अनाज वसूली की योजनाओं के बारे में जो बहस में उठाना चाहता हूँ, उसको उठाने का कई बार प्रयास हुआ था, लेकिन कोरम और समय के अभाव में वह स्थगित होती रही। इस विषय के सम्बन्ध में सब से पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ : मैं ने इस साल के बजट सत्र के प्रारम्भ में सरकार से सवाल किया था कि क्या उस ने विभिन्न राज्यों की अनाज वसूली की योजनाओं का तालनिक अध्ययन कर के कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि खाद्य नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो आवश्यक जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उस के सम्बन्ध में एक तालनिक दृष्टि रख कर जो अध्ययन करना चाहिए, सरकार अब तक वह नहीं कर पाई है।

मैं ने आंकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि विभिन्न राज्यों में अनाज वसूली के क्या लक्ष्य बनाए गए थे और उन लक्ष्यों को कहां तक पूरा किया गया है। उसी तरह मैंने इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि किस दाम से अनाज वसूला गया और किस दाम से सरकार के द्वारा वह बेचा जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली